भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3718
11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

ग्रामीण अवसंरचना में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा

3718**. श्री अनूप संजय धोत्रेः**
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री विजय कुमार दुबेः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री अनन्त नायकः
श्री बलभद्र माझीः
श्री भोजराज नागः
श्री काली चरण सिंहः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेष रूप में क्योंझर और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित ओडिशा में ग्रामीण आवास, पुलों, सिंचाई और कृषि बुनियादी ढांचे जैसे ग्रामीण अवसंरचना में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या क्योंझर और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित ओडिशा में ग्रामीण अवसंरचना और सार्वजनिक संपत्तियों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं या डेमोंस्ट्रेशन परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत, पूर्ण और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी पहलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का, ओडिशा को जारी धनराशि और क्योंझर तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवसंरचना निर्माण, स्थायित्व, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के संदर्भ में इसके तहत हासिल किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार घरेलू इस्पात उत्पादन और क्षमता बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत, 15 राज्यों में 100 कंपनियों की कुल 167 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें ओडिशा की 19 परियोजनाएं शामिल हैं।

जारी...2/-

सरकार विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना और आवास में भी महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, जिससे परियोजना-विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर इस्पात के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़क संपर्क और जल जीवन मिशन के तहत 81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल के पानी की पहुंच का विस्तार स्थायी ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में योगदान दे रहा है। इन पहलों से ओडिशा सहित देश भर में ग्रामीण आवास, पुलों, जल आपूर्ति, सिंचाई और कृषि अवसंरनचा में घरेलू स्तर पर उत्पादित इस्पात की मांग को बनाए रखने की उम्मीद है। तथापि, इस्पात मंत्रालय इन कार्यक्रमों के तहत इस्पात की खपत, प्रदर्शन परियोजनाओं, वित्तीय सहायता अथवा रोजगार सृजन से संबंधित योजना-वार अथवा निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखता है।

*****